चार दिन में सोना-चांदी ऑल टाइम हाई

ग्लोबल टेंशन का असर-सोना-चांदी बेकाबू रफ्तार

29 दिन में सोना 43 हजार महंगा, चांदी 1 .55 लाख ऊपर

नई दिल्ली, 29 जनवरी. सोना और चांदी लगातार चौथे दिन ऐसी रफ्तार से भागे हैं कि बाजार के आम लोग पूरी तरह से हैरान रह गए. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 29 जनवरी को 24 कैरेट सोना एक ही दिन में 11,486 बढ़कर 1,76,121 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. वहीं चांदी 27,666 उछलकर 3,85,933 प्रति किलो हो गई. सिर्फ तीन दिनों में सोना 21,811 और चांदी 68,228 महंगी हो चुकी है.

सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठा राज्यसभा में

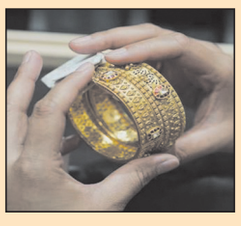

देश में सोने और चांदी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि का मुद्दा आज राज्यसभा में उठा और सरकार से हस्तक्षेप कर लोगों को राहत पहुंचाने की मांग की गई. कांग्रेस के नीरज डांगी ने गुरुवार को शून्य काल के दौरान सदन में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में सोने चांदी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और इनकी कीमतों को बेलगाम छोड़ देना सरकार की नीतिगत विफलता है. उन्होंने कहा कि सोना और चांदी के आभूषण ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है और यह मामला बचत तथा महिलाओं की गरिमा से जुड़ा हुआ है.

साल 2026 के महज 29 दिनों में सोना 42,926 और चांदी 1,55,513 महंगी हो चुकी है. इस तेजी के पीछे केवल डिमांड नहीं, बल्कि ग्लोबल राजनीतिक तनाव, अमेरिकी टैरिफ की आशंका, डॉलर के मुकाबले रुपये की रिकॉर्ड गिरावट और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की भारी खरीदारी जैसे बड़े कारण काम कर रहे हैं. निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की ओर भाग रहे हैं. यही वजह है कि सोना-चांदी अब आम लोगों की पहुंच से तेजी से दूर होते जा रहे हैं और बाजार में 'सेफ हेवन' की होड़ साफ दिखाई दे रही है. सोना और चांदी इस समय सिर्फ कीमती धातु नहीं, बल्कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में सबसे भरोसेमंद निवेश के प्रतीक बन गए हैं. आईबीजे के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 23 जनवरी को 1,54,310 प्रति 10 ग्राम रहा सोना अब 1,76,121 पर पहुंच चुका है. इसी तरह 3,17,705 प्रति किलो रही चांदी अब 3,85,933 पर है. यह उछाल सामान्य बाजार चाल नहीं, बल्कि असाधारण परिस्थितियों का संकेत है. सबसे बड़ा कारण वैश्विक तनाव है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयानों और यूरोपीय देशों को टैरिफ की धमकी ने ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ा दी है.

रुपया 24 पैसे टूटा

मुंबई, 29 जनवरी. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 24 पैसे टूटकर 91.9250 रुपये प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर बंद हुआ. पिछले कारोबारी दिवस पर रुपया 22 पैसे की मजबूती के साथ कारोबार की समाप्ति पर 91.68 रुपये प्रति डॉलर पर रहा था. रुपये में आज बड़ा उतार-चढ़ाव देखा गया. शुरुआती कारोबार में इसमें तेजी थी. यह 8.50 पैसे की बढ़त में 91.60 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और 91.50 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ. लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारतीय पूंजी बाजार में बिकवाली के दबाव में यह 91.9250 रुपये प्रति डॉलर तक टूटकर उसी स्तर पर बंद हुआ. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों तेजी से भी रुपये पर दबाव रहा.

गिरावट से उबरे शेयर बाजार

निजी बैंक और धातु कंपनियों में आई तेजी

बीएसई का सेंसेक्स पहुंचा 82,566 .37 अंक पर

मुंबई, 29 जनवरी. घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को 982 अंक का बड़ा उतार-चढ़ाव देखा गया और शुरुआती गिरावट से उबरकर प्रमुख सूचकांक अंततः हरे निशान में बंद हुए. बीएसई का सेंसेक्स 221.69 अंक चढ़कर 82,566.37 अंक पर पहुंच गया.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 76.15 अंक यानी 0.30 प्रतिशत की बढ़त में 25,418.90 अंक पर रहा. सेंसेक्स 24 अंक की बढ़त के साथ खुला और खुलते ही लाल निशान में चला गया. हालांकि संसद में वित्त वर्ष 20225-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद बाजार में तेजी लौट आयी. एक समय यह 637 अंक टूटकर नीचे 81,707.94 अंक तक उतर गया था. बाद में 82,689.96 अंक तक चढ़ा भी.

टाटा स्टील का शेयर लगभग साढ़े चार प्रतिशत चढ़ा

निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक और स्मॉलकैप 100 सूचकांकों में 0 .20 प्रतिशत की समान मजबूती दर्ज की गयी. धातु, निजी बैंकिंग, रियलटी और तेल एवं गैस क्षेत्रों की कंपनियों में लिवाली का जोर रहा. वहीं, एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, फार्मा, सार्वजनिक बैंकों, स्वास्थ्य, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और रसायन समूहों की कंपनियों में बिकवाली हावी रही. सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील का शेयर लगभग साढ़े चार प्रतिशत चढ़ गया. एलएंडटी और एक्सिस बैंक में साढ़े तीन प्रतिशत के करीब तेजी रही.

नेशनल एसेट ने तीन दिवाला खातों में लाभ दिया

नई दिल्ली, 29 जनवरी. नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने तीन अधिग्रहीत दिवाला कंपनियों के खातों के माध्यम से अब लाभ का वितरण शुरू कर दिया है और सरकार की पूरी प्रतिभूति चुकता कर दी है.

यह जानकारी वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू की अध्यक्षता में कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ बैठक में दी गयी. बैठक को बताया गया कि एनएआरसीएल द्वारा अधिग्रहित खातों की संख्या 29 से बढ़कर 30 हो गई है, जिससे कुल अधिग्रहित ऋण जोखिम का आंकड़ा लगभग 1.63 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. ऐसे खातों की पहचान भी की गई है जो वर्तमान पाइपलाइन में हैं, जिनसे अधिग्रहण का कुल आंकड़ा दो लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच सकता है. वित्त मंत्रालय की गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही की इस पहली बैठक में आगामी तिमाही की आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ तीसरी तिमाही के प्रदर्शन पर चर्चा की गई.

विज्ञप्ति के अनुसार गत आठ अक्टूबर को इससे पिछली तिमाही की समीक्षा के बाद से एनएआरसीएल वसूली में लगभग 1,439 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि हुई है और कुल वसूली 5,496 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है. इस वसूल पूंजी में 4,803 करोड़ रुपये की प्रतिभूति की रसीद (एसआर) के आधार पर प्राप्त राशियां शामिल हैं. बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि एनएआरसीएल ने

तीन खातों में प्रतिभूतियों से जुटाई गयी 100 प्रतिशत सिक्योरिटी रिसीप्ट्स (एसआर) का पैसा प्राप्त कर लिया गया है और इसमें लाभ का अतिरिक्त हिस्सा ऋणदाताओं को वितरित कर दिया गया है. बैठक में उन तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया जिनसे अधिग्रहण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम किया जा सके. विभेदक सुरक्षा संरचनाओं, अतिरिक्त गिरवी और मूल्यांकन पर असहमति के कारण ऋणदाताओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिनकी वजह से अधिग्रहण में अधिक समय लगता है.

सचिव, डीएफएस ने इस बात पर जोर दिया कि अधिग्रहण प्रक्रिया में होने वाली देरी को कम करने के लिए ऋणदाताओं और एनएआरसीएल दोनों को अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि ऋणदाताओं को संयुक्त ऋणदाता बैठक (जेएलएम) में लिए गए निर्णयों पर टिके रहने के धर्म का पालन करना चाहिए. समाधान के मोर्चे पर हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अधिग्रहित खातों की वसूली और समाधान के माध्यम से जनता का पैसा वापस लाने की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है.

भारत-ईयू एफटीए की विशेषज्ञों ने की सराहना

इस समझौते को आर्थिक और भू-राजनीतिक दोनों तरह से सही समय पर उठाया गया कदम बताया

नई दिल्ली, 29 जनवरी भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते के पूर्ण होने पर दुनिया भर में, अंतरराष्ट्रीय मीडिया, विदेशी राजनीतिक नेतृत्व, वैश्विक व्यापार प्रमुखों और सम्मानित नीति विशेषज्ञों ने मज़बूत और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं.

इस समझौते को आर्थिक और भू-राजनीतिक दोनों तरह से ऐतिहासिक, रणनीतिक और सही समय पर उठाया गया कदम बताया जा रहा है. दुनिया के प्रमुख मीडिया संस्थानों ने भारत-ईयू एफटीए की व्यापकता, महत्वाकांक्षा और रणनीतिक समय का उल्लेख किया है. द टेलीग्राफ ने जे स क्रिस्प के मोदी इज़ द रियल विनर इन मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स विद् ईयू शीर्षक से एक लेख में इस समझौते को सभी व्यापार समझौतों की जननी बताते हुए कहा कि भारत इस मामले में असली रणनीतिक विजेता के रूप में उभरा है. अख़बार ने बताया कि यह समझौता ईयू से भारत को होने वाले 96.6 प्रतिशत निर्यात पर टैरिफ को खत्म या कम करता है, जबकि ईयू सात वर्षों में 99.5 प्रतिशत भारतीय सामानों पर टैरिफ कम करेगा.

व्यापार प्रमुख और संगठन

भारत में काम कर रहे यूरोपीय और वैश्विक व्यापार प्रमुखों ने इस समझौते से अत्यंत उ मीद जताते हुए इसे लंबे समय से प्रतीक्षित सफलता बताया. एयरबस में भारत और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया के अध्यक्ष जुर्गन वेस्टरमेयर ने एफटीए को 20 वर्ष की वार्ता के बाद एक बड़ा पल बताते हुए कहा कि यह दोनों पक्षों के लिए अवसरों को बढ़ाने का काम करेगा.

ब्लूमबर्ग ने डैन स्टूमफ के ऑल रोड्स लीड टू मोदी एज़ वर्ल्ड हेजिज ट्रंप शीर्षक से एक लेख में कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ मदर ऑफ ऑल डील्स समझौता एक उभरते हुए पैटर्न का नवीनतम उदाहरण है-भारत देशों के लिए पसंदीदा पार्टनर बन रहा है. द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे वैश्विक टैरिफ बाधाओं के प्रति मध्यम शक्तियों की प्रतिक्रिया के रूप में पेश करते हुए लिखा कि कैसे भारत और ईयू अमेरिकी व्यापार नीतियों से पैदा हुई अनिश्चितता के बीच गठबंधन का विस्तार कर रहे हैं.

परांजपे ने वेकोलि में संभाला तकनीकी दायित्व

तीन दशक के खनन अनुभव के साथ निदेशक का पदभार ग्रहण

डॉ. हेमंत शरद पांडे ने उनका गर्म जोशी से स्वागत किया

नागपुर, 29 जनवरी. वेकोलि में को संदीप एस. परांजपे ने निदेशक (तकनीकी / परियोजना एवं योजना) का पदभार ग्रहण किया.

परांजपे के वेकोलि आगमन पर वेकोलि के निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. हेमंत शरद पांडे ने उनका गर्म जोशी से स्वागत किया. श्री परांजपे ने वर्ष 1991 में रामदेवबाबा कमला नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज, नागपुर विश्वविद्यालय से माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है तथा उन्हें कोयला खनन क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध एवं व्यापक अनुभव प्राप्त है. पाथाखेड़ा एवं सावनेर में 16 वर्षों के भूमिगत खनन अनुभव के साथ-साथ उन्होंने प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण, परियोजना क्रियान्वयन, उत्पादन, खान नियोजन, कोयला गुणवत्ता तथा माइन क्लोजर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गहन विशेषज्ञता अर्जित की है. वेकोलि में निदेशक का दायित्व संभालने से पूर्व कंपनी को महत्वपूर्ण संचालनात्मक एवं रणनीतिक योगदान प्रदान किया.

हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा खंड पर विद्युत रेल परिचालन

अहमदाबाद, 29 जनवरी. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल के हिम्मतनगर और खेड़ब्रह्मा को जोड़ने वाली ऐतिहासिक मीटर गेज रेलवे लाइन, जो एक सदी से भी अधिक समय से साबरकांठा क्षेत्र की जीवनरेखा रही थी, अब आधुनिक ब्रॉड गेज रूप में पुनः खुलने जा रही है.

हिम्मतनगर से खेड़ब्रह्मा के बीच 55.672 किमी नवनिर्मित ब्रॉड गेज रेलखंड का 25 केवी, 50 हर्ट्ज, ए.सी. इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया गया है. हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा मीटर गेज सेक्शन पर 01 जनवरी 2017 से रेल यातायात बंद किया गया था. इस के उपरांत हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा गेज परिवर्तन परियोजना, जो गुजरात के साबरकांठा जिले में 55 किमी से अधिक की दूरी को कवर करती है, इस परियोजना को 2 जून 2022 को ?482 करोड़ की लागत से स्वीकृति मिली थी. प्रधानमंत्री जी द्वारा 18 जून 2022 को इस गेज परिवर्तन का शिलान्यास किया था जिसे लगभग 3 साल के रिकॉर्ड समय पूर्ण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है.

बेंगलुरु में मल्टी-ब्रांड सर्विस शुरू

बेंगलुरु, 29 जनवरी. टोयोटा किर्लोस्कर सुंदरम ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने गुरूवार को बेंगलुरु में अपने पहले मल्टी-ब्रांड रिटेल सर्विस आउटलेट टीसर्व सेलेक्ट की शुरूआत की. टोयोटा किर्लोस्कर सुंदरम ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, किर्लोस्कर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, त्रिचूर सुंदरम संथानम फैमिली और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है. यह नई कंपनी भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार की लगातार प्रगति और ग्राहकों की उम्मीदों को देखते हुए स्थापित की गई ह.

स्कोप-सीबीसी ने आईएसबी से मिलाया हाथ

दीक्षा नेतृत्व क्षमता विकास की अपनी तरह की पहली बड़ी पहल

नई दिल्ली, 29 जनवरी. केंद्रीय लोक उपक्रमों के मंच स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप) और क्षमता निर्माण क्षेत्र पर केंद्र सरकार की एजेंसी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन (सीबीसी) ने दीक्षा नेतृत्व कार्यक्रम के तहत तीसरे बैच के प्रशिक्षण के लिए इंडियन स्कूल ऑफ़ बिजनेस (आईएसबी) के साथ एक करार किया है.

दीक्षता नेतृत्व कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थाओं में भविष्य की नेतृत्व को तैयार करना है. स्कोप की बुधवार को जारी स्कोप के डायरेक्टर जनरल अतुल सोबती, सीबीसी के संयुक्त सचिव जगदीश गुप्ता और आईएसबी के डीन प्रोफेसर मदन पिल्लुटला ने इस करार पर हस्ताक्षर किये.

इस अवसर पर सीबीसी की सदस्य डॉ. अलका मित्तल, सीबीसी के पूर्व चेयरमैन आदिल जैनुलभाई और तीनों संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. दीक्षा (डेवलपमेंट ऑफ़ एस्पिरेशन, नॉलेज, सक्सेशन एंड हार्मनी) नेतृत्व क्षमता विकास की अपनी तरह की पहली बड़ी पहल है जिसे स्कोप और सीबीसी ने मिलकर बनाया है. इसका मकसद सरकारी कार्पोरेट क्षेत्र में उच्च क्षमता के अधिकारियों में, जिनसे बोर्ड लेवल के पदों पर आने की उम्मीद है, उन्नत नेतृत्व क्षमताओं, रणनीतिक सोच और उभरते औद्योगिक परिदृश्य पूरी समझ उत्पन्न करना है.

समाचार विशेष

बिहार कांग्रेस के प्रभारी और अध्यक्ष से नाराजगी

प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के अलावा कांग्रेस का एक भी नेता हवाईअड्डे पर नहीं पहुंचा

पटना. जिस समय भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा था यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को कुर्सी पर बैठाया, उनके पीछे खड़े हुए और उससे पहले कहा कि नितिन नबीन उनके भी बॉस हैं और पूरी पार्टी नितिन नबीन के नाम के नारे लगा रही थी. उसी समय राहुल गांधी द्वारा नियुक्त किए गए बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना पहुंचे. पटना हवाईअड्डे पर उनको रिसीव करने के लिए सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पहुंचे थे. राजेश राम के साथ भी कोई व्यक्ति नहीं था. कांग्रेस का एक भी नेता हवाईअड्डे पर नहीं पहुंचा.

बाद में कांग्रेस की टिकट से लोकसभा का

चुनाव लड़ चुके एक नेता ने सोशल मीडिया पर फोटो डाली और तंज करते हुए लिखा, 'बिहार चुनाव की अपार सफलता के बाद प्रभारी महोदय पहली बार पटना पहुंचे तो हवाईअड्डे पर प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया'.

असल में चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने पता नहीं किस रणनीति के तहत तत्कालीन अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा दिया था और उनकी जगहल राजेश राम को अध्यक्ष बनाया था. इसी तरह मोहन प्रकाश की जगह अल्लावरू प्रभारी बने थे. दोनों की राजनीति का लब्बोलुआब यह था कि कांग्रेस 70 की जगह 61 सीटों पर लड़ी, जिसमें 10 पर दोस्ताना मुकाबला हुआ और 19 की जगह सिर्फ छह सीट जीती. अब वो छह विधायक भी लापता हैं और प्रदेश अध्यक्ष के बुलाए किसी कार्यक्रम में नहीं शामिल होते हैं. खबर है कि ये छह विधायक सत्तारूढ़ गठबंधन में भाजपा या जदयू की ओर जाने का रास्ता तलाश रहे हैं.

यूपी में टलेंगे पंचायत चुनाव?

अप्रैल-मई में मतदान पर संशय

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. क्या ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव तय समय पर हो पाएंगे? या फिर इन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद तक टाल दिया जाएगा?

हालिया प्रशासनिक गतिविधियां और राजनीतिक संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, अप्रैल-मई 2026 में पंचायत चुनाव कराना अब मुश्किल नजर आ रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह जनगणना-2027 है. भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय ने 22 जनवरी को जनगणना का कार्यक्रम जारी कर दिया है. इसके तहत 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक हाउस-लिस्टिंग और फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना की जाएगी. क्या ऐसे में प्रदेश के पास पंचायत चुनाव कराने के लिए पर्याप्त अधिकारी और कर्मचारी बचेंगे?

जानकारी के अनुसार, जनगणना की हाउस-लिस्टिंग में यूपी के 75 जिलों से 50 से 60 हजार शिक्षक, शिक्षा मित्र, लेखपाल समेत भारी संख्या में कर्मचारी लगाए जाएंगे.

जमीन मजबूत करने के लिए हरियाणा मॉडल

चंडीगढ़. विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी भाजपा हरियाणा मॉडल का सहारा ले रही है. इसकी कमान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संभाली है. वे कुछ दिन से पंजाब में सक्रिय दिख रहे हैं और पंजाबियों को बता रहे हैं कि आखिरकार हरियाणा के विकास पथ पर बढ़ने का रोडमैप क्या है.

इसके अलावा भाजपा की नजर पंजाब में विरोधी दलों के असंतुष्ट और हाशिये पर बैठे नेताओं पर भी है. इन नेताओं को भाजपा की नीतियां समझाकर उन्हें भाजपाई बनाया जा रहा है. यह काम भी सीएम सैनी के नेतृत्व में हो रहा है. पंजाब में फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. सत्तारूढ़ आप, कांग्रेस, भाजपा, शिअद समेत अन्य दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं.

अभी तक भाजपा यही दावा कर रही है कि इस बार भी विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी. इसके लिए पंजाब भाजपा के नेता खासे उत्साहित भी दिख रहे हैं. कार्यकर्ताओं ने पंजाबियों से मिलना-जुलना भी तेज कर दिया है. इसी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा इस बार हरियाणा मॉडल रखा गया है. दरअसल, साल 2017 और 2022 में सत्तारूढ़ आप ने अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल का पंजाब में खूब प्रचार किया. इस मॉडल की कई नीतियां पंजाब में लागू करते हुए आप ने साल 2022 में सत्ता पाई. भाजपा भी अब हरियाणा मॉडल के बूते कुछ इसी तरह का प्रयोग पंजाब में करना चाहती है. हरियाणा को इसलिए चुना गया है, क्योंकि भाजपा साल 2014 से हरियाणा में काबिज है और यह राज्य भी कभी पंजाब का ही हिस्सा रहा है. हरियाणा आज भी खुद को पंजाब का छोटा भाई मानता है. हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है और इस बार सूबे के सीएम नायब सैनी पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं.

डबल इंजन सरकार का फायदा बता रहे सैनी

नायब सैनी पिछले कुछ दिन से पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं. हर जगह वे कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आम पंजाबियों से भी मिल रहे हैं. सैनी पंजाबियों को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में डबल इंजन सरकार तेजी से विकास कर रही है. इसी तरह हरियाणा की बड़ी आबादी को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है और इसके लिए हजारों करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है. किडनी रोगियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जा रही है.

विशेष सियासतदान बिछाने लगे सियासी गोटियां, स्वामी प्रसाद ने अभियान शुरू किया

सपा-भाजपा की जंग के बीच तीसरे मोर्चे की घुसपैठ

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू हो गई है. इस बीच सियासी हवा के झोंके भी आने लगे हैं. सियासतदान गोटियां बिछा रहे हैं. नफा-नुकसान के हिसाब से गोलबंदी हो रही है. इसमें दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का नया मोर्चा तैयार होने लगा है.

बसपा से भाजपा होते हुए साइकिल पर सवार रहे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अब नई पार्टी बना चुके हैं. वह अपनी जनता पार्टी के झंडे तले पुराने बसपाइयों को इकट्ठा कर रहे हैं. आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर खुद को कांशीराम का सियासी वारिस साबित करने में जुटे हैं. वह महारैली के जरिए दलितों को बसपा छोड़ खुद के साथ जुड़ने की अपील कर रहे हैं.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर नए मोर्चे को ताकत देने के संकेत दिए हैं. कभी सपा के साथ रहे जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय चौहान भी बिरादरी के दम पर बांह बटोर

रहे हैं. कांग्रेस ने महारैली शुरू कर दी है तो लोकसभा चुनाव परिणाम से उत्साहित सपा पीडीए पंचायत के जरिए जनता के बीच उतरी है. आगामी चुनाव के मद्देनजर अभी तक भाजपा और सपा के बीच आमने-सामने की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन प्रदेश की सियासत में तीसरा मोर्चा तैयार करने की बेताबी भी साफ दिख रही है. इसके पीछे पिछड़ों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों का वोटबैंक हैं. तीसरे मोर्चे को भरोसा है कि वह इस वोटबैंक के दम पर सियासी वैतरणी पार कर लेगा.

यह भी कहा जा रहा है कि तीसरे मोर्चे की खिचड़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी बेचैन हैं.

कई नेता संपर्क में - सूत्रों का यह भी कहना है कि इस मोर्चे में विभिन्न सियासी दलों के वे कद्दावर नेता भी शामिल हो सकते हैं, जो अपनी पार्टी में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. अन्य नेता अभी खुले तौर पर नए मोर्चे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ताल ठोंक रहे हैं.

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में तीसरे मोर्चे का ही भविष्य है. वह समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं के लगातार संपर्क में हैं. अभी तो शुरुआत है जल्द ही इसके परिणाम भी दिखेंगे. वह दावा करते हैं कि खुद को बड़ा दल बताने वाली पार्टियों के दर्जनभर से ज्यादा नेता उनके संपर्क में हैं.